6803 Written Answers ASADHA 1, 1889 (SAKA) Written Answers 6804

संबाज करूपाण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेपु गुह): (क) से (ग). यह मुचना एकवित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी।

भारत बेरल एण्ड ड्रम मुनुफेक्वरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का काली सूची में रखा जाना

3308 श्री प० ला० बारूपाल श्री मुद्रिका सिंह :

क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली सूची में रखी गई फर्म का नाम उस पर लगाये गये सभी ग्ररोपों से न्यायालय ढारा ससम्मान बरी किये जाने तथा काली सूची से उसका नाम निकालने का ग्रादेग दिये जाने पर भी उस सूची में दर्ज रहता है;

(ख) किसी फर्म का नाम काली सूची में कितने समय तक रखा जा सकता है तथा फर्मों को काली सूची में रखने सम्बन्धी सिद्धांत क्या हैं; ग्रौर

(ग) क्या बम्बई की भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैकचरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटड नामक फर्म का नाम ग्रब भी काली सूची में है जब कि बम्बई उच्च न्यायालय ने उसे ससम्मान बरी कर दिया है ?

पेट्रोलियम झौर रसायन, योजना तथा समाज कल्पाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमेया) (क) काली सूची से सम्बन्धित आदेश तब तक लागू रहता है जब तक कि इस का प्रतिसंहरण (Revoke) न कर दिया जाये । यदि न्यायालय ने फर्म को उस पर लगाये गये उन ग्रारोपों से, जिन के कारण काली सूची से सम्बन्धित आदेश जारी किये गये थे, बरी कर दिया हो, तो काली सूची के आदेश हटाने पर विचार करने के लिये यह एक कारण हो सकता है। यदि न्याया-लय ढ़ारा काली सूची में सम्बन्धित ग्रादेश की कार्यान्विति को निलम्बित कर दिया जाता है तो इसे कुछ काल के लिये स्थगित करना हो गया।

(ख) काली सूची के जारी रहने की कोई निष्चित समयावधि नहीं है। प्रत्येक कैस के तथ्यों के ग्राधार पर ग्रवधि निर्धारित की जाती है। सरकार विभागों / उपकर्मों से व्यापार करने में कदाचारों के कारण काली सूची के ग्रादेश जारी किये जाते हैं।

(ग) जुलाई, 66 में पंजाब हाई कोर्ट ने भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफ्रैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिभिटेड के काली सूची में रखे जाने से सम्बन्धित दिनांक 25-1-64 के ग्रादेश को ग्रागामी ग्रादेशों तक जारी रखने का निदेश किया था। ग्रतः काली सूची के ग्रादेश को स्थगित कर दिया गया है।

Barrels for I.O.C.

3309. Shri Ram Dhan: Shri N. K. P. Salve:

Will the Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Oil Corporation Ltd. had invited through Tender No. OP|TEN-7|65 for their requirement of oil barrels for the year 1966-67;

(b) whether it is also a fact that orders for the supply of barrels against the above tender were placed by them on Messrs. Hind Galvanising and Engineering Co. Pvt. Ltd., and Messrs. Standard Drum and Barrel Mfg. Co. in spite of the fact that the prices quoted by Messrs. Bharat Barrel and Drum Mfg. Co. Pvt. Ltd. were lower;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the amount of loss sustained by Indian Oil Corporation Ltd, in placing the orders at higher prices; (e) whether Government are aware of the fact that the above two firms supplied to the Indian Oil Corporation against the above tender barrels fabricated out of hot rolled sheets and billed them for barrels fabricated out of cold rolled sheets; and

(f) if so, whether any investigation has been made in this regard.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Planning and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah): (a) Yes, Sir.

(b) Orders placed on Messrs. Hind Galvanising & Engineering Co. Pvt. Ltd., were for Calcutta requirements for which they had tendered the lowest quotation. Orders placed on Messrs. Standard Drums & Barrels Manufacturing Co. were for part of the Bombay requirements for which they had submitted the next lower tender, the quotation of M[s. Bharat Barrels' being the lowest.

(c) After a careful consideration of all aspects of the bids, the Indian Oil Corporation decided to place orders for the Bombay requirements on M[s. Standard Drums & Barrels Manufacturing Co. and two other suppliers.

(d) The extra expenditure incurred as a result of the decision in (c) is Rs. 1.77 lakhs.

(e) and (f). The matter is being investigated by the Indian Oil Corporation and the correct position will be ascertained and placed on the table of the Sabha.

Dr. Dharma Teja of M/s. Jyanti Shipping Co.

3310. Shri Mrityunjay Prasad: Shri Valmiki Choudhary: Shri Shiv Chandrika Prasad:

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 872 on the 30th May, 1967 and state:

(a) the year-wise amount of Wealth-Tax and Income-Tax levied on Dr. Dharma Teja Jyanti Shipping Co. and realised;

(b) whether an enquiry is being held in respect of his movable and immovable properties and original source of his income; and

(c) the periods for which the statements and annual balance sheets of income, expenditure, profit and loss of the Jyanti Shipping Co. were prepared and published.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Provisional assessments have been made in respect of Wealth-Tax. The Wealth-Tax levied and realised is as under:---

Year	Tax levied	Tax realised.
	Rs.	Rs
1962-63 .	22,880	22,880
1963-64 .	1,27,951	1,27,951
1964-65 .	2,60,802	2,38,122
1965-66 .	2,60,802	2,60,802

Regular assessments for Wealth-Tax are pending. As regards Income-tax, no assessment has been made so far.

(b) Yes, Sir.

(c) Balance Sheets and Profit and Loss accounts of the Jayanti Shipping Co., have been published for the financial years ending 31-3-1962, 31-3-63, 31-3-1964 and 31-3-1965.

जाली सिम्के

3311. श्री प॰ ला बारूपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैाली ग्रठन्नियां, जिन पर भूतपूर्वप्रधान मंत्री श्री नेहरू का ग्रीष श्रंकित है, चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन सिक्कों के चलने के लिये उत्तरदायी गिरोह का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी हैं; धौर